

दि का र्मिक पोस्ट

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 12, अंक : 35

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 26 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

महासागरों को चढ़ा रिकॉर्ड बुखार= 21.1 डिग्री पर पहुंचा समुद्र की सतह का औसत तापमान



नई दिल्ली। पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी अब सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं रही, महासागर भी लगातार तपने लगे हैं। ऐसा ही कुछ इस महीने भी देखा गया, जब 22 अगस्त 2026 को वैश्विक स्तर पर समुद्र की सतह का औसत तापमान बढ़कर रिकॉर्ड 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने पुष्टि की है कि यह दर्ज जलवायु इतिहास का अब तक का सबसे अधिक दैनिक तापमान है, जिसने मार्च 2024 में बने पिछले ऑल-टाइम रिकॉर्ड (21.09 डिग्री सेल्सियस) को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि कॉपरनिकस का यह आंकड़ा 1979 से उपलब्ध रिकॉर्ड पर आधारित है।

इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह अगस्त में बना है। आमतौर पर वैश्विक स्तर पर समुद्र की सतह का औसत तापमान मार्च और अप्रैल में सबसे अधिक रहता है। इसके बावजूद अगस्त में तापमान का पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देना दर्शाता है कि महासागर किस असाधारण गर्मी से गुजर रहे हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक दिन की गर्मी नहीं है। 2026 में दुनिया के बड़े हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान लगातार सामान्य से अधिक रहा है। ऐसे में नया रिकॉर्ड महासागरों पर बढ़ते दबाव का एक और स्पष्ट संकेत है। रुझानों को देखें तो इस समय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में मजबूत अल नीनो विकसित हो रहा है, जो समुद्र के तापमान को और बढ़ा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक, आने वाले महीनों में अल नीनो के और मजबूत होने की आशंका है। कॉपरनिकस की मौसमी भविष्यवाणी प्रणाली भी संकेत दे रही है कि यह घटना कई दशकों में देखे गए सबसे मजबूत स्तरों तक पहुंच सकती है। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागर की मौजूदा गर्मी को केवल अल नीनो से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए दशकों से इंसानों की वजह से जलवायु में हो रहे बदलाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि भी जिम्मेवार है। यानी अल नीनो पहले से गर्म हो चुके महासागर में और गर्मी जोड़ रहा है। यानी बढ़ते इंसानी उत्सर्जन ने समुद्रों में पहले से ही इतनी गर्मी भर दी है कि अब यह नया उबाल आ गया है। कॉपरनिकस में जलवायु रणनीति प्रमुख सामंथा बर्गेंस के मुताबिक, यह रिकॉर्ड ऐसे महासागर का स्पष्ट संकेत है जो लगातार बढ़ते दबाव में है। समुद्र का तापमान बढ़ने के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे भी बढ़ रहे हैं। दुनिया में समुद्री हीटवेव वाले दिनों की संख्या 1990 के दशक की शुरुआत से तीन गुणा से अधिक हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि समुद्र की बढ़ती गर्मी का संकट केवल समुद्री जीवों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तटों पर बसे शहरों, छोटे द्वीपीय देशों और उन करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है,

जिनका जीवन और भविष्य समुद्र से जुड़ा है।

गर्म पानी फैलता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और तटीय इलाकों में बाढ़ तथा कटाव का खतरा गहराता जाता है। साथ ही, समुद्री हीटवेव पहले से कहीं अधिक तीव्र और बार-बार आ सकती हैं। इस बढ़ती गर्मी की मार प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के मैदानों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ती है। इनके कमजोर पड़ने से मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का जीवन संकट में आ सकता है, जिसका सीधा असर मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर निर्भर लाखों परिवारों की आजीविका पर पड़ेगा। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। गर्म महासागर वातावरण में अधिक गर्मी और नमी पहुंचाते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानों के और अधिक तीव्र होने की आशंका बढ़ सकती है। दूसरी ओर, समुद्र की बढ़ती गर्मी उनकी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता को भी कमजोर कर सकती है। यानी, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण ढालों में से एक खुद कमजोर पड़ रही है, और इसका खामियाजा आखिरकार इंसानों को ही भुगतना पड़ सकता है। वैज्ञानिक फिलहाल निगरानी कर रहे हैं कि समुद्र की सतह का यह रिकॉर्ड तापमान कुछ समय की असामान्य स्थिति है या आने वाले दिनों में भी बना रहता है। लेकिन एक बात साफ है, महासागर अब केवल गर्म नहीं हो रहे, वे लगातार बढ़ते जलवायु दबाव का सामना कर रहे हैं। समुद्र धरती की गर्मी का बड़ा हिस्सा अपने भीतर समेटते हैं और मानव जीवन को सहारा देने वाले अनगिनत पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए समुद्र की सतह पर दर्ज हुआ यह नया रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस बदलती जलवायु की चेतावनी है जिसका असर आखिरकार इंसानी बस्तियों, भोजन, आजीविका और जीवन पर पड़ता है। ऐसे में अगर समय रहते हमने पृथ्वी के इस बुखार को कम नहीं किया, तो इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि संकाय के विद्यार्थियों, किसानों और कृषि स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों से किया संवाद

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा शक्ति को उन्नत खेती से जोड़ने, किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादों के निर्यात पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बदलते दौर में खेती का भी समय बदला है। नई तकनीक और नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ा रहना आवश्यक है। युवा कृषि संकाय की पढ़ाई कर अपने लिए भविष्य के लिए नए रास्ते बनाएं।

लेह में प्रदूषण का कहर जारी, 187 एक्यूआई; दिल्ली-फरीदाबाद समेत 35 शहरों में हवा चिंताजनक



लेह सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 24 अगस्त 2026 को एक बार फिर देश में लेह सबसे प्रदूषित रहा। इस दौरान वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 187 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। हालांकि कल (23 अगस्त) लेह में सूचकांक 207 दर्ज किया गया था। मतलब कि कल से वहां प्रदूषण के स्तर में 20 अंकों का सुधार आया है। रुझानों में यह भी सामने आया है कि लेह की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह हावी है। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है।

लेह में स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा

से 4,500 फीसदी अधिक है। दूसरी तरफ देश में मदिकेरी की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 12 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर लेह की तुलना मदिकेरी से करें तो वहां स्थिति 15.5 गुणा खराब है। दिल्ली में कल से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जहां कल एक्यूआई 96 दर्ज किया गया था, जो आज बढ़कर 111 पर पहुंच गया। मतलब की पिछले 24 घंटों में वहां वायु गुणवत्ता में 15 अंकों का उछाल आया है। इसके साथ ही दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। 2026 के दौरान दिल्ली में साल का सबसे साफ दिन 09 जुलाई को दर्ज किया गया, जब एक्यूआई 48 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह 08 जुलाई 2026 को सूचकांक 59 और 07-24 अगस्त को 63 रिकॉर्ड किया गया। वहीं 04 अगस्त और 22 जुलाई 2026 को सूचकांक 64 दर्ज हुआ। दूसरी तरफ 18 जनवरी 2026 को दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित दिन दर्ज किया गया,

जब एक्यूआई बढ़कर 440 तक पहुंच गया था।

दिल्ली की तरह ही फरीदाबाद में भी कल से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। फरीदाबाद में जहां कल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 133 दर्ज किया गया था, जो आज बढ़कर 135 पर पहुंच गया। इसके साथ ही 2 अंक के उछाल के साथ फरीदाबाद में आज भी एक्यूआई मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24 अगस्त 2026 को 239 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां करीब 36.4 फीसदी शहरों में हवा साफ है। वहीं 49 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 14.6 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज हवा साफ है। कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्थिति जस की तस है। वहीं दूसरी तरह संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में 13.3 फीसदी की गिरावट आई है। रुझानों के मुताबिक मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में कल से करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जोकि चिंता का विषय है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले

में भागलपुर (172) दूसरे जबकि अंबाला (160) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह टोंक (140) चौथे स्थान पर है। खोरा (139) डू नोएडा में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो पांचवें और छठे पायदान पर हैं। पलवल (139) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में भिवानी (138), फरीदाबाद (135) और मानेसर (133) शामिल हैं। रुझानों में सामने आया है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के पांच शहर (अंबाला, पलवल, भिवानी, फरीदाबाद, मानेसर) शामिल हैं। विश्लेषण से यह भी पता चला है कि भागलपुर, खोरा, फरीदाबाद, मानेसर, चरखी दादरी, खैरथल, बड़ौत, पानीपत, जींद, दिल्ली, बर्नीहाट (असम), गुरुग्राम और मुजफ्फरनगर आदि शहरों की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) हावी हैं। वहीं अंबाला, टोंक, नोएडा, पलवल, भिवानी, पीथमपुर, वातवा, छपरा, नारनौल, श्री गंगानगर, सिवान, जोरपोखर, अजमेर, गांधीनगर, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, ग्रेटर नोएडा, अलवर और जोधपुर आदि शहरों में पीएम10 से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

राखी से पहले हजारों श्रमिकों के लिए उमंग और उल्लास लेकर आई संबल योजना की राशि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्रमिकों की सेवा, कल्याण और खुशी हमारे लिए सबसे पहले है। हमारे श्रमिक अपने खून-पसीने से विकसित मध्यप्रदेश की नींव तैयार कर एक-एक ईंट जोड़ रहे हैं। हर परिस्थिति में श्रमिकों की कठिनाई को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों पर विपत्ति आने, घर चलाने वाले के असामयिक निधन, अचानक आर्थिक संकट आने पर लोग साथ छोड़ दें, परंतु हमारी सरकार कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 मुश्किल समय में श्रमिकों को आर्थिक सहारा भी देती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के श्रमिक बंधुओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रक्षाबंधन से पहले श्रावण के अंतिम सोमवार को श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि की 11वीं किश्त के रूप में 203 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से पात्र हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश के 9 हजार 149 संबल हितग्राहियों को मिली यह राशि इन सभी परिवारों में आनंद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि संबल योजना ने प्रदेश के 1 करोड़ 84 लाख से अधिक श्रमिकों को सहारा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कठिन समय में जब सभी रास्ते बंद होंगे, तब भी सरकार उनके साथ खड़ी है। यह राशि दुख की घड़ी में बड़ी राहत लेकर आती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर जेब में पैसे हों, तो अनेक विपत्तियों का सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछला बैकलॉग खत्म करते हुए निर्बाध रूप से श्रम सहित सभी विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिलों से बीसी से जुड़े श्रमिक हितग्राहियों को श्रावण सोमवार और आने वाले रक्षाबंधन पर्व की मंगलकामनाएं दी।

श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां श्रम शक्ति संहिता लागू की गई है। इसके साथ ही सरकार ने श्रम स्टार रेटिंग की शुरुआत भी हमने की है, ताकि श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि हम श्रमिकों को उनके हुनर परिष्कृत कर मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्रमिकों को सहकारिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से श्रमणा योजना की शुरुआत की गई है।

कार्बन समस्थानिकों से खुलासा- अनाज के बड़े दाने इंसानी चयन नहीं, बल्कि मौसम से हुए बड़े, वैज्ञानिकों का दावा

मुंबई। करीब 11 हजार साल पहले दक्षिण-पश्चिम एशिया में इंसानों ने धीरे-धीरे जंगली पौधों को उगाना शुरू किया। गेहूं, जौ, दालों और फल देने वाले पौधों की देखभाल बढ़ने लगी। लंबे समय में यही बदलाव खेती और कृषि समाजों के विकास का आधार बना।

अब प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने खेती की शुरुआत को समझने के पुराने विचारों पर सवाल उठाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआती दौर में अनाज के दाने बड़े होने का कारण जरूरी नहीं कि इंसानों का चुनाव या पौधों में आनुवंशिक बदलाव हो। इसके बजाय, पानी और मौसम जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों ने दानों के आकार को प्रभावित किया हो सकता है। जंगली गेहूं और जौ के पौधों में आमतौर पर छोटे दाने होते हैं। इसके अलावा, उनके पौधे की एक संरचना, जिसे 'रैचिस' कहा जाता है, पकने के बाद आसानी से टूट जाती है। इससे जंगली पौधे के बीज जमीन पर गिर जाते हैं और प्राकृतिक रूप से फैलते हैं। इंसानों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक नहीं थी। खेती करने वालों के लिए ऐसे पौधे ज्यादा उपयोगी थे जिनके बीज पकने के बाद भी पौधे से जुड़े रहें। धीरे-धीरे ऐसे पौधों का चयन हुआ जिनमें मजबूत रैचिस था। यही बदलाव आगे चलकर घरेलू यानी पालतू फसलों की पहचान बना। पुरातत्वविदों को शुरुआती नवपाषाण काल के कुछ स्थलों पर बड़े आकार के अनाज के दाने मिले थे। इसलिए लंबे समय से माना जाता रहा कि ये दाने इस बात का संकेत हैं कि इंसान उस समय बड़े दानों वाले पौधों का चयन कर रहे थे। लेकिन नई जांच इस तस्वीर को बदल रही है। शोधकर्ताओं ने दक्षिणी लेवांत के दो महत्वपूर्ण स्थलों, एल-हेम्मेह और शरारा, से मिले अनाज का अध्ययन किया। यहां शुरुआती दौर में जौ और एमर गेहूं के पौधों में अभी भी जंगली पौधों जैसी विशेषताएं मौजूद थीं। इन पौधों में बीज गिराने वाली कमजोर रैचिस संरचना बनी हुई थी। इसका मतलब है कि उस समय तक इन फसलों में घरेलू पौधों की एक महत्वपूर्ण पहचान विकसित नहीं

हुई थी। फिर भी एक दिलचस्प बात सामने आई। एक ही जगह से मिले अनाज के दानों के आकार में काफी अंतर था। कुछ दाने बिल्कुल जंगली अनाज जैसे छोटे थे, जबकि कुछ दाने बाद में मिलने वाले घरेलू अनाज जितने बड़े थे। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए जले हुए अनाज के दानों में मौजूद स्थिर कार्बन समस्थानिकों का अध्ययन किया। पौधे जिस वातावरण में बढ़ते हैं, खासकर उन्हें कितना पानी मिलता है, उसका असर उनके कार्बन समस्थानिकों पर पड़ता है। अध्ययन में पाया गया कि बड़े जौ के दानों में ऐसे संकेत मिले जो बताते हैं कि वे अपेक्षाकृत अधिक नमी वाली परिस्थितियों में उगे थे। दूसरी ओर, छोटे दाने ज्यादा सूखी परिस्थितियों में उगे थे। इससे वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। संभव है कि बड़े दाने इसलिए नहीं बने क्योंकि इंसानों ने जानबूझकर बड़े दानों वाले पौधों को चुना था। वे केवल इसलिए बड़े हुए क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए ज्यादा पानी मिला था। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस समय पौधों में दिखाई दे रहा बड़ा आकार 'विकासात्मक लचीलापन' यानी पर्यावरण के अनुसार पौधे की विशेषताओं में बदलाव का परिणाम हो सकता है। इसका मतलब है कि पौधे के जीन बदले बिना भी अच्छी परिस्थितियों में उसके दाने बड़े हो सकते हैं। इस निष्कर्ष से खेती के शुरुआती इतिहास को समझने का तरीका बदल सकता है। संभव है कि बड़े दानों के लिए आनुवंशिक चयन बाद में शुरू हुआ हो। पहले इंसानों ने ऐसे पौधों को पसंद किया होगा जिनके बीज पकने के बाद भी पौधे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बड़े और अधिक उपयोगी दानों के लिए चयन तेज हुआ होगा।

वन संपदा, जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वनकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल, जंगल, वानस्पतिक संपदा और वन्य प्राणियों की रक्षा करने में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने नैसर्गिक सुंदरता के साथ मध्यप्रदेश को वनों का अनुपम खजाना दिया है। वन भारत और दुनियाभर में मध्यप्रदेश की पहचान हैं। हमारे वनकर्मों पूरी लगन से इसकी रक्षा करते हैं। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पदोन्नति के फैसले का लाभ वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार है। सुशासन के लिए हर क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में वन विभाग में पदोन्नत शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पदोन्नति शासकीय सेवकों का उसके काम के प्रति लगन और समर्पण का सम्मान है। वन विभाग के 4 हजार 506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया है। सभी विभागों में कर्मचारियों को मिली पदोन्नति से मन संतोष से भरा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन विभाग के लिए 25 हजार 389 पद स्वीकृत हैं। अभी 18 हजार से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हम वन प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हमने पदोन्नति के साथ ही खाली हुए पदों को भरने के लिए नई भर्ती के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति से वन विभाग में वर्षों के इंतजार का फल मिला है। जिन्हें पदोन्नति मिली है उनमें 188 सहायक वन संरक्षक, 2,821 वनपाल, 761 उप वन क्षेत्रपाल तथा अन्य संवर्ग के 736 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पदोन्नत अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके परिजनों के सहयोग और त्याग के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को 'प्रकृति पुत्र' और 'ग्रीन सोलजर्स' की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके बीच आकर मन प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को भारत जैसे मेगा-बायोडायवर्स देश और समृद्ध जैव-विविधता की विरासत मिली है। वन अमले के पुरुषार्थ से मध्यप्रदेश वन एवं वन्य जीव संरक्षण का रोल मॉडल बना है। प्रदेश की पहचान जल, जंगल

और जीव से है और वन विभाग ने इनके संरक्षण में मिसाल कायम की है। इसी पुरुषार्थ के कारण मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, वल्कर स्टेट और अब चीता स्टेट का गौरव मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज मध्यप्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में पूरे देश अग्रेसर है। प्रदेश के जंगलों में अब जंगली भैंसें भी आ चुके हैं। मध्यप्रदेश के वन और वन्य जीवों की दुनिया मुरीद है। हमारे वनकर्मों पूरी प्रतिबद्धता के साथ जंगल, पहाड़, वन और नदियों की रक्षा करते हैं। वनकर्मों हमारी वन संपदा की सुरक्षा की मजबूत दीवार की तरह हैं, जो वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ वन क्षेत्र में निवासरत आबादी की भी चिंता करते हैं। मनुष्य का जीवन और जंगल एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारा प्रयास है कि जैसा हमने पाया है, उससे और बेहतर हम भावी पीढ़ी को सौंपें। ईश्वर की कृपा से मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। कोई ग्लेशियर नहीं होने पर भी हमारी नदियां जलराशि से सदैव समृद्ध रहती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे पास अगली पीढ़ी को सबसे अच्छा तोहफा सौंपने का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि विकास तभी पूर्ण होगा, जब जंगल और जैव-विविधता सुरक्षित रहें, नदियां संरक्षित रहें और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित हो। प्रमुख सचिव, वन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की वन सम्पदा और वन्य प्राणियों का संरक्षण मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विशेष रुचि का विषय है। मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72 प्रतिशत वनों के आच्छादित है। यहां 9 टाइगर रिजर्व, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्यप्रदेश की पहचान हैं। पर्यटन क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का हृदय क्षेत्र है। इतनी बड़ी संख्या में वन और वन्य प्राणियों की संख्या के आधार पर मध्यप्रदेश लंग्स ऑफ इंडिया भी है। कुछ महीने पहले रातापानी (सर वीएस वाकणकर) और माधव टाइगर रिजर्व, डॉ. भीमराव आम्बेडकर अभयारण्य सहित प्रदेश के पहले तासी कंजर्वेशन रिजर्व का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चीता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, गजरक्षक (एआई प्रणाली) से हाथियों की निगरानी, पीएम गतिशक्ति परियोजना के लिए वन मानचित्रों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक और नवाचार लगातार संचालित हो रहे हैं।

भारत का ई-सफर पीएम ई-ड्राइव योजना में कानपुर नगर आगे, देहात उपेक्षित; अवैध चार्जिंग और परमिट संकट से बढ़ी अव्यवस्था



कानपुर उन गिने-चुने उत्तर प्रदेश के शहरों में है जिनके लिए वाहन-उत्सर्जन का शहर-विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए किए गए सोर्स एपॉर्शनमेंट अध्ययन (2022) के अनुसार शहर में पीएम 2.5 उत्सर्जन में सड़क की धूल के बाद वाहनों की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) उत्सर्जन में करीब 85 प्रतिशत हिस्सा अकेले वाहनों से आता है। अच्छी बात यह है कि सीपीसीबी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक विश्लेषण (2021 से 2023) शहर में वायु प्रदूषण में 19 फीसदी की कमी बताता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कानपुर भी स्मार्ट सिटी की सूची में दर्ज है लेकिन सड़कों पर बेलगाम ट्रैफिक और ई-रिक्शा और ईवी तिपहिया वाहनों ने अपना डेरा जमा रखा है और ईवी में दोपहिया वाहन भी धीरे-धीरे यहां लोकप्रिय हो रहा है। कानपुर के सनिगवां के रहने वाले मोहित सविता डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि जबसे उन्होंने ईवी स्कूटर खरीदा है तबसे उनका ग्राँसरी डिलवरी का काम बढ़िया

चलने लगा है। वह बताते हैं कि 200 रुपये रोजाना करीब वह ईंधन का बचा लेते हैं। 4 घंटे की चार्जिंग में 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। वह चार्जिंग घर पर ही करते हैं। उन्होंने बताया कि चार्जिंग के लिए अभी बाहर कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसकी सख्त जरूरत है। कानपुर में ईवी स्कूटर या दोपहिया वाहन बेचने वाले निजी संचालकों के पास उनकी खुद की गाड़ी के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन है लेकिन पब्लिक एक्सेस चार्जिंग स्टेशन की कमी है। अभी हाल ही में सिटी क्लब के पास शुरू हुए एक निजी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है कि जिसमें पब्लिक एक्सेस है। वहां माल दुलाई रिक्शे को चार्ज करते हुए सुनील मौर्या ने कहा कि इस सुविधा की शहर को बहुत जरूरत है क्योंकि अवैध चार्जिंग स्टेशन बहुत ज्यादा पैसा वसूलते हैं। प्रति घंटे 70 से 80 रुपये ई-रिक्शा चार्जिंग का ले लेते हैं।

राजधानी लखनऊ में 27 मई 2026 की सीएम-समीक्षा बैठक के अनुपालन दस्तावेज के अनुसार, पीएम ई-ड्राइव योजना के पहले चरण में कानपुर नगर और कानपुर देहात, दोनों जनपद शामिल हैं, लेकिन दोनों के बीच आवंटन में बड़ा अंतर है। कानपुर नगर में 12 चार्जिंग स्थल स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 4 कैटेगरी-ए (सरकारी/केंद्रीय परिसर) और 8 कैटेगरी-बी (सरकार-नियंत्रित उच्च-यातायात स्थल, जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल) श्रेणी में हैं।

इसके उलट कानपुर देहात में केवल 2 स्थल स्वीकृत हुए हैं, दोनों ही कैटेगरी-ए श्रेणी में, यानी 238 प्रदेशव्यापी स्वीकृत स्थलों में सबसे कम हिस्सा पाने वाले जनपदों में कानपुर देहात शामिल है। हालांकि, अभी धरातल पर काम होना बाकी है। वहीं, कानपुर ई-बसों के डिपो में भी अभी 100 बसें हैं। जिसमें 3 किलोमीटर का 10 रुपये और अधिकतम 28 किलोमीटर का 45 रुपये तक किराया वसूला जाता है। डिपो पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि यहां दो साल पहले 3 बसें चार्जिंग के दौरान ही जल गई थीं। इनमें से अभी तक दो ही बसें रिप्लेस हुई हैं। ईवी को बढ़ावा देने के बाद कानपुर में सबसे बड़ी चुनौती सीएनजी चालकों के सामने उभर कर आई है। सीएनजी के ड्राइवर से जुड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष दुबे ने डाउन टू अर्थ को बताया कि ईवी में रिक्शा और तिपहिया को इतनी छूट दी जा रही है कि सीएनजी के पुराने विक्रम शेयरिंग ऑटो चालकों पर आजीविका का संकट आकर खड़ा हो गया है। वह समझाते हैं कि 3,300 सीएनजी तिपहिया विक्रम वाहनों की संख्या घटकर अब 1,500 से भी नीचे आ गई है। यह 50 फीसदी की कमी इसलिए आई क्योंकि इन वाहनों पर जो 4 लाख रुपये की परमिट बनती थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब सात लाख रुपये की इस वाहन की कीमत घटकर एक लाख भी नहीं मिल रही है। स्कैप में भी इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि इससे ई-वाहनों पर शिफ्ट किया जा सके। वहीं संजीवनगर ई-बस डिपो के पास कई ई वाहन रिक्शा चालक या तो घर पर खुद से रिचार्ज करते हैं या फिर अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी चार्ज करवाते हैं। आरटीओ पांडेय कहते हैं कि ईंधन के लिए सीएनजी बेहतर है लेकिन उसकी आपूर्ति के लिए हमें आयात निर्भर रहना पड़ता है, जबकि हम ऊर्जा नवीकरणीय माध्यमों से धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ईवी को उसके साथ जोड़ना अग्रिम नीति होगी इसलिए सीएनजी के बजाए ईवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों के लिए हर शहर में एक सर्वे की जरूरत है कि किसी शहर में असल में कितने रिक्शों को सड़क पर अनुमति दी जा सकती है। इसमें भी परमिट व्यवस्था होनी चाहिए या फिर मोटर अधिनियमों में इसको रेगुलेट करने के लिए प्रावधान होने चाहिए।

लाड़ली बहनों को राखी के शगुन के साथ मिली लाड़ली बहना योजना की राशि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहन-बेटियां हमारे घर-आंगन की रौनक हैं। बहन-बेटियों का मान-सम्मान और इनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हर महीने बहनों से उनकी रक्षा का वादा पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने सौगात मिल रही है। उन्होंने कहा कि शारदा मां के आशीर्वाद से मैहर अद्भुत स्थान है। बुंदेलखंड की वीरता के प्रतीक आल्हा-ऊदल मां शारदा के अनन्य भक्त हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उदारता और रिश्तों का सम्मान करने की परम्परा है। हम भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम अनुसार पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमने आज ही मैहर से प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को नैहर की नेग (राज्य सरकार का उपहार) दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मैहर में हुए राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में मां शारदा भवानी के दर्शन किए। इसके बाद इसी जिले की प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी सुश्री अनन्या अवधिया और सुश्री उन्नति पांडे के साथ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किश्त और रक्षाबंधन के विशेष शगुन के 250 रुपये (कुल 1750 रुपये) के रूप में 2 हजार 148 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से बैंक खातों में अंतरित किये। जून 2023 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से अगस्त 2026 तक 39 किश्तों में लाड़ली बहनों के खातों में 63 हजार 248 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना बहनों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए सशक्त बनी है। रक्षाबंधन का धागा भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। राज्य सरकार बहनों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत हर माह बहनों का राशि भेजी जा रही है। प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख लाड़ली बहनों का आशीर्वाद सरकार को मिल रहा है। हर साल रक्षाबंधन से पहले बहनों को 250 रुपये का शगुन भी भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर जिले में लगभग 256 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले की विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों तथा योजनाओं की उपलब्धि पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी बहनें विवाह के पूर्व माता-पिता के घर को संवारती हैं और विवाह के बाद पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेती हैं। बहनों का यह त्याग वंदनीय है। भारतीय संस्कृति में मां-बेटियां परिवारों की धुरी हैं। माताएं अपनी चिंता नहीं कर पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। राज्य सरकार ने अगले 5 साल तक लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की राशि देने का निर्णय कैबिनेट में लिया है। अगले 5 वर्ष में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि बहनों को मिलेगी।